यह माना गया कि आईडीबीआई द्वारा ऋण पुनर्वित्त किए जाने के बाद, यदि उत्तरदाताओं ने समय पर किस्तों का भुगतान किया तो अपीलकर्ता 9J प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का हकदार था और यदि वे ऐसा करने में चूक करते हैं तो 12J प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का हकदार था। इसलिए, अपीलकर्ता उत्तरदाताओं द्वारा किस्तों का भुगतान करने में चूक करने के बाद पुनर्वित्त राशि पर 12J प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का हकदार है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने गलती से यह माना है कि वृद्धि के बाद बैंक दर के अनुसार, निगम पुनर्वित्त ऋण पर 13J प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का हकदार है। बंधक विलेख में ऐसा कोई खंड नहीं है जो उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करता हो। यदि आई.डी.बी.आई. द्वारा पुनर्वित्त नहीं किया गया तो बैंक दर में वृद्धि ने ऋण पर ब्याज दर को प्रभावित किया। या पुनर्वित्त ऋण अपीलकर्ता द्वारा आई.डी.बी.आई. को वापस कर दिया गया था। नतीजतन, मेरी राय है कि अपीलकर्ता इस दर पर ब्याज वसूलने का हकदार नहीं है। 13 जे प्रतिशत का और विद्वान ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष इस सीमा तक रद्द किए जाने योग्य है।

(15) उपरोक्त कारणों से, मैं अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि अपीलकर्ता आकस्मिक शुल्क और विविध खर्चों का हकदार है। मैं प्रति आपत्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि अपीलकर्ता पुनर्वित्त ऋण पर 13J प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का हकदार नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ■ मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ता हूं।

समक्ष एस.एस.सोढ़ी से, जे.

रमेश चंदर- याचिकाकर्ता.

बनाम

भूषण लाल, प्रतिवादी।

सिविल पुनरीक्षण सं. 1984 का 1005.

8 मई 1984

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 21(2) - एक अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है - एक अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी द्वारा उसमें

दर्ज किए गए साक्ष्य - ऐसे साक्ष्य को क्या अमान्य माना जा सकता है - साक्ष्य की डेनोवो रिकॉर्डिंग –चाहे आवश्यक हो.

अभिनिर्णित, माना गया कि किसी न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में एक आपत्ति पर अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, तीन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है, अर्थात् (1) आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई थी, (2) इसे जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया गया था और ऐसे मामलों में जहां मुद्दों को ऐसे निपटान पर या उससे पहले निपटाया जाता है और (3) परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। मामला कुछ समय तक सब जज प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित रहा और दोनों पक्षों ने गवाहों की जांच की और बिना किसी आरक्षण के सबूत पेश किए और सबूत के निष्कर्ष पर ही पहले से दर्ज किए गए सबूतों पर आपत्ति लेने की मांग की गई। यह किसी भी तरह से आपत्ति उठाने का सबसे पहला अवसर नहीं था और इससे भी अधिक, अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के कारण न्याय में कोई विफलता नहीं हुई है। इस प्रकार, यदि एक अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मुकदमे में, साक्ष्य को एक अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी द्वारा दर्ज किया जाता है, तो क्षेत्राधिकार की किसी भी अंतर्निहित कमी को लागू करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता है और इस प्रकार दर्ज किए गए साक्ष्य को शून्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसके लिए डेनोवो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है। .

(पैरा 5, 8 और 9)।

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री के आदेश में संशोधन हेतु। एम. पी. मेहंदीरत्ता, एचसीएस, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, हांसी ने दिनांक 14 मार्च, 1984 को आदेश दिया कि इस स्तर पर प्रतिवादी उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी की अदालत में दर्ज किए गए साक्ष्य पर आपत्ति नहीं उठा सकता है और मामले को 22 मार्च, 1984 अंतिम बहस के लिए स्थगित कर दिया गया है।.

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री के आदेश में संशोधन हेतु। एम. पी. मेहंदीरत्ता, एचसीएस, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, हांसी ने दिनांक 14 मार्च, 1984 को आदेश दिया कि इस स्तर पर प्रतिवादी उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी की अदालत में दर्ज किए गए साक्ष्य पर आपत्ति नहीं उठा सकता है और मामले को 22 मार्च, 1984 के लिए स्थगित कर दिया गया है। मामले में अंतिम बहस के लिए.

सिविल विविध. क्रमांक 1812-सीआईआई/84।

सीपीसी की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय पुनरीक्षण याचिका के अंतिम निपटान तक उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी की अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करेगा।

डी. एस. बाली, अधिवक्ता, - याचिकाकर्ता के लिए।

एच. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. एल. सरीन, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

(1) एक अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मुकदमे में, क्या एक अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य को अमान्य माना जाएगा, जिससे उसकी डेनोवो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी? यहीं पर खड़ा हुआ विवाद है.

(2) यहां मुकदमा 19 अगस्त 1981 को सक्षम न्यायालय, अर्थात् अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में स्थापित किया गया था, और मुद्दे 12 दिसंबर, 1981 को तय किए गए थे, लेकिन कोई सबूत मिलने से पहले, जून, 1982 में। दर्ज किया गया, मामला अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद मुकदमे के सभी साक्ष्य इस न्यायालय में दर्ज किए गए। साक्ष्य 31 जनवरी, 1984 को समाप्त हुआ। तब यह पता चला कि इसके आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, मुकदमा अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय था। परिणामस्वरूप फ़ाइल जिला न्यायाधीश को भेजी गई, जिन्होंने इसे अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।

(3) अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष प्रथम श्रेणी साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की गई। इस आधार पर मांग की गई कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य किसी ऐसे न्यायालय द्वारा लिए गए हैं जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए, इस पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसे ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था ■ * और - यही वह आदेश है जिसे अब चुनौती दी गई है।

(4) आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं ली गई हो , और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों

का निपटारा किया जाता है, ऐसे समझौते पर या उससे पहले, और जब तक इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो।"

(5) एलआर और अन्य द्वारा मृत कूइलन अनसीन की बेटी पक्थुम्मा और अन्य बनाम कूइलन अनसीन की कुंतलन कुट्टी (1) में, न्यायालय के पास आपत्तियों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 (2) में निहित समान प्रावधानों पर विचार करने का अवसर था। **>** न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के लिए। यह देखा गया, "मुकदमा करने की जगह पर आपत्ति पर अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके, इसके लिए निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: -

(1) आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई थी।

(2) यह जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया गया था और ऐसे मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा ऐसे निपटारे से पहले या उससे पहले किया जाता है

- ' ■ment.

(3) परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

ये तीनों स्थितियाँ सह-अस्तित्व में होनी चाहिए।"

(6) याचिकाकर्ता के वकील श्री डी.एस. बाली ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी और आर्थिक क्षेत्राधिकार की कमी के बीच अंतर निकालने की मांग की। तर्क यह है कि जहां पूर्व पर आपत्तियों को माफ किया जा सकता है, वहीं बाद वाले के मामले में यह मूल तक जाता है, अर्थात, न्यायालय की क्षमता और इसलिए, किसी भी पक्ष के किसी भी कार्य या चूक से पराजित नहीं किया जा सकता है। मुकदमा। यहां हीरा लाई पाटनी बनाम श्री काली नाथ (2) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मांगा गया था, जिसमें न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति से निपटते हुए, यह देखा गया था, "यह अच्छी तरह से तय है किसी अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति किसी मामले की सुनवाई करने की अदालत की क्षमता पर आपत्ति के समान नहीं है। किसी मामले की सुनवाई करने की न्यायालय की क्षमता न्यायक्षेत्र की जड़ तक जाती है, और जहां इसकी कमी है, यह अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी का मामला है। दूसरी ओर, किसी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार पर आपत्ति को माफ किया जा सकता है और इस सिद्धांत को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 21 जैसे अधिनियमों द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है।

(7) इस परिच्छेद को पढ़ने में यह ध्यान रखना उचित होगा कि "क्षेत्राधिकार की अंतर्निहित कमी" का अर्थ यह बताया गया था कि "अदालत मामले को जब्त नहीं कर सकती थी क्योंकि

विषय वस्तु उसके अधिकार क्षेत्र या प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से विदेशी थी।" जिस समय मुकदमा संस्थित किया गया था या डिक्री पारित की गई थी, उस समय मृत था, या ऐसा कोई अन्य आधार था जिसके प्रभाव से न्यायालय को मुकदमे की विषय वस्तु या उसके पक्षों के संबंध में पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र की कमी हो सकती थी।

(8) इस आलोक में विचार करने पर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21(2) के प्रावधानों के संदर्भ में भी, यहां अधिकार क्षेत्र की किसी अंतर्निहित कमी को लागू करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता है।

(9) यह देखा जाएगा कि मामला डेढ़ साल से अधिक समय तक अधीनस्थ न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में लंबित रहा। दोनों पक्षों ने गवाहों की जांच की और बिना किसी संदेह के सबूत पेश किए। यह केवल साक्ष्य के निष्कर्ष पर था कि पहले से ही दर्ज किए गए साक्ष्य पर आपत्ति की मांग की गई थी। यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के पास इसे उठाने का सबसे पहला अवसर नहीं था और इससे भी अधिक, याचिकाकर्ता के वकील अधीनस्थ न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के कारण न्याय की विफलता की ओर इशारा नहीं कर सके।

(10) इस प्रकार आक्षेपित आदेश आर में कोई हस्तक्षेप नहीं करने की गारंटी देता है, जिसके परिणामस्वरूप इसे लागत सहित खारिज कर दिया जाता है। वकील की फीस रु. 300.

अस्वीकरण

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नूंह